क्या बढता हुआ संरक्षणवाद वैश्वीकरण के अंत का सूचक है?

अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिण्टन ने इतिहास को साक्षी मानते हुए कहा था- "आज तक किसी भी पीढ़ी को ऐसा सुअवसर प्राप्त नहीं हुआ जो हमें प्राप्त हुआ है; वह है- एक ऐसी वैश्विक अर्थव्यवस्था के निर्माण का जिसमें कोई पिछड़ा हुआ नहीं रहेगा। यह हमारे लिये गंभीर उत्तरदायित्व निभाने का एक बेहतरीन अवसर है।" इसी को हम वैश्वीकरण कहते है, जो विश्व के एकीकरण की एक प्रक्रिया है। इस एकीकृत विश्व में लोग वस्तुओं और सेवाओं से लेकर विचारों एव नवाचारों तक का आदान-प्रदान करते हैं।

अब, इस संदर्भ में अगर हम वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दृष्टिकोण की बात करें तो उनके विचारों का मुख्य सार 'एकला चलो' अर्थात् 'अमेरिका फर्स्ट' की नीति है। इसके तहत विभिन्न वस्तुओं, सेवाओं एवं नागरिकों के निर्बाध आवागमन पर प्रशुल्क, कोटा एवं वीज़ा के माध्यम से विभिन्न प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिये गए हैं। इसी नीति के तहत ट्रंप सरकार ने प्रशान्त-पारीय, उत्तरी अटलांटिक एवं अटलांटिक-पारीय देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतो जैसे- टीपीपी, एनएएफटीए और टीटीआईपी को भी समाप्त करने की घोषणा कर दी है। इन सभी कदमों का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी उत्पादकों, व्यापारियों एवं कार्मिकों को आयात प्रतिस्पर्द्धा से संरक्षण प्रदान करना है, यही विचारधारा संरक्षणवाद कहलाती है।

क्लिंटन बनाम ट्रंप अर्थात् वैश्वीकरण बनाम संरक्षणवाद की यह दुविधा अमेरिका ही नहीं वरन सम्पूर्ण विश्व में विद्यमान है। वर्तमान वैश्विक परिवेश को अगर हम व्यापक दृष्टि से देखें तो सम्पूर्ण विश्व मुख्यतः दो भागों में बंटा हुआ नज़र आता है-

संरक्षणवादी पश्चिम- इसमें पश्चिमी दुनिया के विकसित देश सम्मलित हैं, जो संरक्षणवादी विचारधारा को प्रोत्साहन दे रहे हैं, मसलन- ब्रिटेन का 'ब्रेक्ज़िट', अमरिका का 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' बाई 'अमेरिका फर्स्ट'। कुछ इसी तरह विश्व के विकसित एवं उभरते देशों के समूह जी-20 ने भी संरक्षणवादी नीतियों को अपनाने पर बल दिया है। यूरोपीय संघ के देशों द्वारा टीटीआई एवं टीपीपी का विरोध यह स्पष्ट करता है कि सम्पूर्ण पश्चिमी जगत वैश्वीकरण के विरोध में लामबंद हो चुका है, इसी का परिणाम है कि पेरिस इटली की ऊर्जा-फर्म के मुँह पर दरवाज़ा बन्द कर रहा है, तो अमेरिकी सीनेटर अपने बंदरगाहों पर विदेशी नागरिकों एवं माल के विरोध में मार्च निकाल रहे हैं एवं यूरोप में पहुँचने वाले चीनी माल को टैरिफ से रोककर स्थानीय उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है।

वैश्वीकृत पूर्व- इसमें एशिया, मध्य एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप के विकासशील एवं अल्पविकसित देश शामिल हैं। जहाँ मुक्त व्यापार समझौते, उदारीकृत कर व्यवस्था एवं निवेश आकृष्ट करने हेतु नियमों के सरलीकरण की प्रक्रिया आज भी बदस्तूर जारी है। यह यहाँ की जनता एवं सरकार का वैश्वीकरण में बढ़ते विश्वास को अभिव्यक्त करता है। हम निस्संकोच कह सकते हैं कि आज वैश्विक अर्थव्यवस्था एशिया में स्थानांतरित हो चुकी है। इस क्षेत्र में सर्वप्रमुख है- 'एशियन टाइगर्स' जो इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार की सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरा, विश्व का सबसे बड़े बाज़ार एवं मैन पावर से युक्त भारत है, जो स्वयं में एक विश्व है। इसकी विविधता ने ही यहाँ 'वसुधैव कुटुम्बकम' की संस्कृति को पल्लवित एवं पोषित किया है। चीन एवं जापान इस क्षेत्र की महाशक्तियाँ हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था निर्यातोन्मुखी है। वहीं दूसरी ओर अफ्रीका एवं एशिया के विकासशील व अल्पविकसित राष्ट्र हैं, जो विकास के लिये विदेशी निवेश एवं विदेशी व्यापार पर निर्भर हैं। अतः संरक्षणवादी नीतियाँ इन राष्ट्रों के लिये वज्रपात के समान होंगी।

उपर्युक्त दोनों स्थितियों का विश्लेषण करने के पश्चात् अगर हम यह सोचें कि ऐसा अचानक क्या हो गया कि वैश्वीकरण के स्थान पर संरक्षणवाद नीति-निर्माताओं की नीतियों का मुख्य आधार बन गया है तो जवाब है- 2007-08 की वैश्विक आर्थिक मंदी जिसने दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों को अपनी आर्थिक नीतियों पर पुनर्विचार करने हेतु बाध्य कर दिया, और इस विचार-मंथन से जो निष्कर्ष उभरकर आया है, वह है- 'वैश्वीकरण का अंत और संरक्षणवाद का प्रारम्भ।'

यह सत्य है कि संरक्षणवाद लघुकाल के लिये लाभप्रद हो सकता है लेकिन इसके साथ यह भी सत्य है कि इससे महज घरेलू समस्याओं का ही समाधान हो पाएगा, जबकि वैश्विक समस्याएँ अधिक विकराल रूप धारण करके हमारे समक्ष उपस्थित होंगी, मसलन- जब बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ किसी एक देश में सिमट जाएंगी तो पहले से जिन-जिन देशों में कार्यरत थीं, वहाँ अनुत्पादकता, बेरोज़गारी एवं अभावों को छोड़कर जाएंगी, जबकि अपने गृह राष्ट्र में ये अनावश्यक बोझ के समान होंगी। इसी प्रकार, अगर ट्रंप सरकार अमेरिका में आई-फोन का निर्माण करना चाहे तो कच्चे माल एवं सस्ते श्रम जैसी अनेक समस्याओं से जूझकर जिन आई-फोन्स का उत्पादन होगा वे इतने महँगे होंगे कि आम नागरिक की पहुँच से दूर हो जाएंगे। अतः आज विश्व इस हद तक एकीकृत हो चुका है कि अनेक वस्तुओं का उत्पादन राष्ट्रों पर निर्भर करता है जैसे- फोर्ड कार, सोनी म्यूजिक सिस्टम एवं अनेक मशीनों का भविष्य भी धर्मसंकट में फँस जाएगा। सारांशतः कहें तो अनेक कम्पनियों को अपने उत्पादों के लिये बाज़ार नहीं मिलेंगे, वहीं कई बाज़ारों को उत्पाद नहीं मिलेंगे। ऐसी स्थिति में यह घोषित करना कि वैश्वीकरण अपने अंत की ओर उन्मुखी है, एक अपरिपक्व सोच होगी।

वैश्वीकरण महज मुक्त सीमाओं या मुक्त व्यापार से युक्त आर्थिक एकीकरण तक सीमित नहीं रहा है वरन् इससे विविध रूपों में विश्व का एकीकरण किया है जैसे-

वैचारिक वैश्वीकरण

इसमें समस्त इन्टरनेट उपयोगकर्ता सम्मलिति हैं, जो एक ऐसे वशि्व की वकालत करते हैं जो अधकि खुला एवं अधकि कनेक्टेड हो।

नव-आर्थकि वैश्वीकरण
इसमें ई-कॉमर्स में सलंग्न एक लाख से अधकि कंपनयिाँ सम्मलिति हैं, जो वैश्वीकरण की ओर अधकि उदार एवं वशि्व को ओर अधकि करीब लाने की ओर उन्मुख हैं ताकि वैश्विकि अवसरों का लाभ उठाकर स्वयं को अधकि सशक्त बनाया जा सके।

सामाजकि वैश्वीकरण
आज वशि्व के सभी नागरकि व्यापार, शकि्षा, अनुसंधान एवं रोज़गार हेतु वदिशों में नविास कर रहे है। ऐसे नविासी अपने गृहराष्ट्र से भी सम्बद्ध होते हैं जो दोनों देशों के समाजों के मध्य कड़ी का कार्य करते हुए समाज के वैश्वीकरण को सफल बनाते हैं।

राजनीतकि वैश्वीकरण
वशि्व के लगभग सभी राष्ट्रों में सभी देशों के नागरकि नविास कर रहे हैं। इन नविासी नागरकिों को उन देशों में मतदान का अधकिार भी प्राप्त है, जनिके माध्यम से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की नीतयिों को प्रभावति कर रहा हैं। ऐसे में संरक्षणवाद कहाँ तक सफल हो पाएगा, यह तो भवषि्य के गर्भ में ही छपिा है।

इस वशि्लेषण के पश्चात् हम यह नषि्कर्ष तो कतई नहीं नकिाल सकते कि वैश्वीकरण अन्तर्मुखी है। माना कि पश्चमिी देशों में नविश एवं रोज़गार में कमी आई है, लेकनि संरक्षणवाद को नई वैश्वकि व्यवस्था के रूप में प्रचारति करना पश्चमिी देशों की दोगली नीतिका परचिायक है। पश्चमिी देशों की मुक्त व्यापार वरिोधी नीतिके पीछे मुख्यतः संरक्षणवादयिों एवं वहाँ की जनता का बेरोज़गारी एवं वेतन-कटौती को लेकर भय है, जसिके परणिामस्वरूप आज पूरा पश्चमिी जगत मुक्त व्यापार के वरिोध में सड़कों पर उतर आया है। अतः संरक्षणवादी वचिारक यह मानते हैं कि प्रत्येक सरकार को देशहति में अर्थव्यवस्था एवं नागरकिों को संरक्षण प्रदान करने हेतु कुछ वैधानकि प्रतबिंध लगाने का अधकिार होना चाहयि। संरक्षणवादी व्यवस्था का अध्ययन करने के पश्चात् हम कह सकते है कि-

संरक्षणवाद दीर्घकालकि वृद्धि हेतु आवश्यक है
1870-90 के काल में यूरोप में आर्थकि एवं औद्योगकि वृद्धि के लयि संरक्षणवाद को आवश्यक समझा जाता था। इस काल में जहाँ जी.एन.पी. एवं औद्योगकि वृद्धि दर क्रमशः 2.61 प्रतशित एवं 3.8 प्रतशित प्रतवर्ष थी, वहीं उदारीकरण के पश्चात् ये दरें घटकर क्रमशः 1.71 एवं 1.8 प्रतशित हो गईं। यह तथ्य स्वयं में वैश्वीकरण पर पुनर्वचिार करने हेतु पर्याप्त है।

शशिु उद्योगों के संरक्षण हेतु
संरक्षणवादी वचिारक वकिास की तीव्र प्रतस्पिर्द्धा से नवीन उद्योगों को सरक्षण प्रदान करना आवश्यक मानते हैं जैसा कि ब्रटिेन ने औद्योगकि क्रान्ति हेतु एवं अमेरकिा ने आर्थकि स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु संरक्षणवादी नीतयिों का आश्रय लयि।

राजनीतकि स्वतंत्रता हेतु आर्थकि स्वतंत्रता प्राथमकि शर्त
यह बहुत ही सामान्य एवं सार्वभौमकि सत्य है कि कोई भी राष्ट्र तब तक राजनीतकि रूप से स्वतंत्र एवं सम्प्रभु होकर नर्णिय नहीं कर सकता, जब तक वह आर्थकि रूप से अन्य राष्ट्रों पर नर्भिर है। अतः वैश्वीकरण वैश्वकि वति्त तो उपलब्ध करवाता है लेकनि कमज़ोर राष्ट्र इस एवज में अपनी सम्प्रभुता खो बैठते हैं।

आर्थकि सशक्तीकरण
संरक्षणवादी वचिारक संरक्षणवाद को एक राष्ट्र की स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लयि भी आवश्यक मानते हैं। इसके माध्यम से जहाँ कोई देश प्रशुल्क, कोटा, वीज़ा एवं अन्य नयिमों के माध्यम से अपना व्यापार घाटा कम कर सकता है, तो वहीं रोज़गार व औद्योगकि वृद्धि दर को बढ़ा भी सकता है।

अतः हम कह सकते है, कि एक देश की स्थानीय समस्याओं के लघुकालकि नरािकरण हेतु संरक्षणवाद महत्त्वपूर्ण है, लेकनि इसे वैश्वीकरण के 'साइड-इफेक्ट' के नविारण हेतु रामबाण औषधि समझना हमारे लयि एक ऐतहिासकि सद्धि हो सकता है।

नषि्कर्ष
आज हमें आवश्यकता है एक ऐसी सन्तुलति व्यवस्था की जसिका दृष्टकिोण वैश्वकि हो एवं क्रयिान्वयन स्थानीय हो अर्थात् 'ग्लोकल एप्रोच' जसिमें 'थकि ग्लोबल' एवं एक्ट लोकल' पर बल दयिा जाता है। 'ग्लोकल' वास्तव में आर्थकि गतविधियिों का वैश्वकि एकीकरण है। इसका उद्देश्य दुनयिा का कोई भी उत्पादक वशि्व के कसिी भी कोने में सस्ती एवं बेहतर तकनीक से उत्पादन करे और उसे दुनयिा के कसिी भी बाज़ार में बेचकर वाजबि लाभ कमाए। अतः सारांश में कह सकते हैं कि 'ग्लोकल' में 'वसुधैव-कुटुम्बकम' का भाव नहिति है। जसिमें अतीत का अनुभव, वर्तमान की ताकत एवं भवषि्य की चुनौतयिों से नपिटने का समाधान समाहति है। हमारे समक्ष 'ग्लोकल' दृष्टकिोण का सबसे सफल उदाहरण स्वयं महात्मा गांधी हैं, जन्हिोंने यह स्वीकार करते हुए कहा कि-

"मैं, ऐसा घर नहीं चाहता जो चारों-ओर से दीवारों से घरिा हो और जसिकी खड़कियाँ जाम हो चुकी हों, वरन् मैं एक ऐसा खुला घर पसंद करूँगा जहाँ चारों ओर की स्वस्थ हवाएँ बहें।"

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/What-rising-protectionism-is-indicative-of-the-end-of-globalization